भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2115

15.03.2021 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में अचानक आने वाली बाढ़ों से निपटने की तैयारी

2115. श्री शमशेर सिंह ढुलो:
डा. अमी याज्ञिक:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 2021 में हिमनदीय आपदा और निकटवर्ती राज्यों पर इसके प्रभावों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो आपदा न्यूनीकरण और आपदा के लिए तैयारी के उपायों समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष, 2014 से अब तक विशेषज्ञों से हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने के बारे मे कोई चेतावनी या सिफारिशें प्राप्त की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : सरकार ने दिनांक 07 फरवरी, 2021 को ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जल-ग्रहण क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना का संज्ञान लिया है। इस हिमस्खलन की घटना के कारण ऋषि गंगा नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो गई और एक कार्यशील लघु जल-विद्युत परियोजना बहकर नष्ट हो गई। अचानक आई इस बाढ़ ने धौली गंगा नदी के किनारे तपोवन में स्थित निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजना को भी प्रभावित किया। इस दुर्घटना में 72 लोगों की जानें गईं और 132 लोग अभी भी लापता हैं। आरंभ में, दुर्घटना स्थल के आस-पास के 13 गावों का संपर्क टूट गया। इन गावों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक आपूर्तियां और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जिलों को हाई-अलर्ट पर रखा गया। एहतियाती उपाय के रूप में, कई ग्रामवासियों को निकालकर गांव खाली कराया गया और बाढ़ के पानी को ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचने से रोकने के लिए प्रवाह की ओर के 2 बांधों को खाली कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), भारतीय सेना आदि के साथ मिलकर राहत और बचाव उपायों में समन्वय स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अक्तूबर, 2020 में ''हिमानी झीलों के फटने से आई बाढ़ का प्रबंधन'' (जीएलओएफ) शीर्षक से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों की विवेचना शामिल है। तथापि, विशिष्ट स्थानों में जोखिमों के लिए विशेष निगरानी करना, डेटा को व्याख्यायित करना तथा विशेष चेतावनियां देना एक चुनौतीपूर्ण एवं उभरता हुआ विषय है

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) द्वारा चमौली जिले में दिनांक 07 फरवरी, 2021 को धौली गंगा में आई अचानक बाढ़ के कारणों की भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, वाडिया हिमालयी भूगर्भ विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय दूरसंवेदी संस्थान सहित विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों द्वारा की जा रही जांच में सहयोग दिया जा रहा है। यूएसडीएमए द्वारा इस आपदा के कारणों की समीक्षा करने तथा इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु दीर्घकालिक कार्यनीति तैयार करने के लिए सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में एक बहु-सांस्थानिक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।

(ग) और (घ) : यूएसडीएमए को दिनांक 07 फरवरी, 2021 की आपदा के संबंध में किसी एजेंसी, संस्थान अथवा व्यक्ति से कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई थी। हिमनदों का वैज्ञानिक अध्ययन देश के विभिन्न संगठनों द्वारा कराया जा रहा है जिनमें ये शामिल हैं - (i) हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एसएएसई), (ii) भारतीय दूरसंवेदी संस्थान (आईआईआरएस), (iii) वाडिया हिमालयी भूगर्भ विज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी), (iv) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), (v) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई), (vi) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), (vii) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) और (viii) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई)।

राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने वर्ष 2014 से हिमालयी हिमनदों का अध्ययन किया है और लाहौल-स्पीति में झील में परिसमाप्त होने वाले हिमनदों की भी झील क्षेत्र एवं आयतन की दृष्टि से उनमें होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए निगरानी की जा रही है। उसने उनमें से एक हिमनद की संभावित संवदेनशीलता की सूचना दी है। एनसीपीओआर ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में हिमांश नाम से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) तथा विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी करके संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में अत्याधुनिक मापन और मॉडलिंग का कार्य शुरू करने हेतु एचआईसीओएम (हिमालय निम्नताप मण्डलीय प्रेक्षण और मॉडलिंग) नामक एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय पहल की शुरूआत की है।

****